

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

**हरियाणा सरकार**  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2022

**संख्या 28/आ0-1/पं0अ0 1/1914/धा0 59/2022.**— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब मीठा (उत्पादन) नियम, 1955, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम पंजाब मीठा (उत्पादन) हरियाणा संशोधन नियम, 2022 कहे, जा सकते हैं।  
(2) ये जून, 2022, के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
2. पंजाब मीठा (उत्पादन) नियम, 1955 में, नियम 4 में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) हरियाणा राज्य में वार्डनरी स्थापित करने के लिए आवेदक द्वारा अपना संयंत्र स्थापित करने से पूर्व आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। वैधता की विनिर्दिष्ट अवधि के साथ कतिपय निबन्धनों तथा शर्तों सहित आशय पत्र जारी किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा। आशय पत्र के लिए फीस पहली बार के लिए एक लाख रुपये होगी तथा वार्डनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र के पुनः विधिमान्यकरण के लिए फीस पिछले फीस का 110 प्रतिशत होगी।”

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY  
DATED THE 10<sup>TH</sup> JUNE, 2022**

**HARYANA GOVERNMENT  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT  
Notification**

The 10<sup>th</sup> June, 2022

**No.28/X-1/P.A.1/1914/S.59/2022.-** In exercise of the powers conferred under section 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Sweets (Manufacture) Rules, 1955, in their application to the State of Haryana, namely :-

1. (1) These rules may be called the Punjab Sweets (Manufacture) Haryana Amendment Rules, 2022.  
(2) They shall come into force with effect from the 12<sup>th</sup> day of June, 2022.
2. In the Punjab Sweets (Manufacture) Rules, 1955, in rule 4, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(iv) A letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a Winery in the State of Haryana before he starts putting up his plant. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a specified period of validity and shall be issued with the permission of Government. Fee for letter of intent shall be rupees one lac for the first time and the fee for revalidation of letter of intent for setting up winery shall be 110% of the previous fee.”.

**ANURAG RASTOGI,**  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.